अरक्षित

वे रोज़ आते हैं
काले नकाबों में, चिकने शरीर, लम्बे बलिष्ठ
पहचाने नहीं जाते।
जब मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूं
तो हाथों से फ़िसल जाते हैं
और भाग जाते हैं अंधेरे में अचीन्हें,
इस तरह वे रोज़ आते हैं।

और मैं भयातुर प्रतीक्षा में
अपनी सुरक्षा के उपाय सोचता हूं
जबकि मैं जनता हूं
कि आत्म-रक्षा के समूचे शस्त्र
जो मुझको विरासत में मिले थे
पुराने पड़ गए हैं, कुण्ठित हो चुके हैं
अब मेरा सब कुछ अरक्षित है
मेरा शरीर, शरीर की संभावनाएं
मेरे संकल्प, आकांक्षाएं, स्थापनाएं
अस्तित्व की सहजताएं
इस तरह वे रोज़ मेरी नंगी
भुजाओं से निकल जाते हैं
और मेरे हाथों में
अपने चिकने शरीरों की मतली-भरी
दुर्गन्ध छोड़ जाते हैं
इस दुर्गन्ध को लेकर
मैं जाऊं तो किधर जाऊं

बाहर जाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे
बच्चे दूध पीना छोड़ देंगे।

और जब पार्क के सारे गुलाबों पर
मेरे हाथों की दुर्गन्ध फैल जाएगी
तो लड़कियां उदास हो जाएंगी
और जब मेरी मां को
मेरे शरीर से अपने दूध की गंध नहीं आएगी
तो वह मुझे पहचानने से इन्कार कर देगी

नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा
भीतर तो मैं अरक्षित हूं
बाहर अजनबी बन जाऊंगा।
लेकिन-
मैं इन सारी आशंकाओं के साथ
बाहर आता हूं
और एक जलूस में शामिल हो जाता हूं
नारे लगाता हूं

और अपने शरीर को सुरक्षित पाता हूं
मेरी मां मुझे स्वीकार लेती है
काले नकाबपोशों के रहस्य बतलाती है
और उनसे लड़ने के तरीके सिखाती है।

-कुमार विकल

पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन साम्राज्यवादी व पूंजीवादी हैं

उत्तराखंड समेत भारत के विभिन्न राज्यों में ''पर्यावरण को बचाने के नाम'' पर गैर सरकारी संगठन समेत राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जनता को कई तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें व गरीब मुल्कों के पूंजीपति वर्ग दोनों मिलकर मुनाफ़े की अंधी हवस में प्रकृति का मनमाने ढंग से दोहन कर रहे हैं। हजारों वर्षों से जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों को इसलिए जल-जंगल-जमीन से बेदखल किया जा रहा है कि जंगलों के नीचे खनिज पदार्थ का खजाना है। मध्य भारत (मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश आदि) के भारत के पूंजीपति वर्ग ने मिलकर लूटा है। सबसे ज़्यादा जंगल और नदियों को नुकसान पहुंचाया है। गैर वैज्ञानिक तरीके से सारे मानकों को ताक पर रखकर प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।

परंतु ये तथाकथित ''पर्यावरण बचाने'' वाले संगठन कभी भी पूंजीपति वर्ग व उसकी राजनीतिक पार्टियों को निशाना नहीं बनाते हैं। उल्टा जनता को हीनता में लाने का काम करते हैं। हमेशा इनके साहित्य व कार्यक्रमों में जनता को पर्यावरण बचाने की सीख दी जाती है। पॉलिथीन का प्रयोग मत करो, पेड़ मत काटो, नदियों में कूड़ा-कचरा मत फ़ेंको, आदि-आदि। जबकि टनों के हिसाब से उद्योगपति अपने उद्योगों का कचरा नदियों में डालते हैं। खनिज पदार्थ व उद्योग लगाने के नाम पर हजारों पेड़ों को काटा जाता है। बड़े-बड़े बांध बनाने के लिये सारे वैज्ञानिक मानकों को ताक पर रखकर नदियों व पहाड़ों को बर्बाद किया जा रहा है।

'नदी बचाओ', 'हिमालय बचाओ', 'जंगल बचाओ',व 'पहाड़ बचाओ' आदि, भांति-भांति के गैर सरकारी संगठन कभी भी प्रकृति के सबसे बड़े दुश्मनों को चिन्हित कर निशाने पर नहीं लेंगे क्योंकि गैर सरकारी संगठनों को खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां पैदा करती है। सरकारें भी कई सारी योजनाओं को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू करती है तो भला ये अपने आकाओं को कैसे नाराज कर सकते हैं या उनके खिलाफ़ जा सकते हैं।

उत्तराखंड में आजादी के संघर्ष से पृथक उत्तराखंड की मांग तक बड़े-बड़े आंदोलन हुए। चिपको आंदोलन, शराब के खिलाफ़ आंदोलन में महिलाओं ने शानदार भूमिका अदा की। यह राज्य आंदोलनों की भूमि होने के कारण यहां 49000 एनजीओ रजिस्टर्ड है जबकि उत्तराखंड में 17000 गांव हैं। प्रत्येक गांव पर लगभग 3 एनजीओ आ रहे हैं। यह इसलिए भी किया जा रहा है कि जनता का गुस्सा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई व पलायन पर बनते हुए मुनाफ़े पर टिकी हुई पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की ओर न बढें। संघर्षशील जनता को सुनहरे मकड़जाल में फ़ंसाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि सामाजिक काम भी हो रहे हों और पांच सितारा होटलों का आनंद भी लिया जा रहा है।

कॉप-20 शिखर सम्मेलन में इवो मोरालेस के भाषण के अंश-''बहनों-भाइयों, हम ऐसा कोई जलवायु समझौता स्वीकार नहीं कर सकते जो पूंजी को लाभ पहुंचाने, मुट्ठीभर लोगों को खुशहाल बनाने और लुटेरी उपभोक्तावादी वृद्धि के लिये धरती और मानवता को मौत के मुंह में धकेलती हो। हम यहां जीवन के हक़ में जलवायु समझौता करने आये हैं व्यापारियों और पूंजीवादी व्यवसायियों के लिये नहीं।'' अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पर्यावरण के नुकसान को रोकने पर सेमिनार, सम्मेलन हो रहे हैं, जो दुनिया में पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे गरीब मुल्कों को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने देशों में पेड़ उगायें, उसका मुआवज़ा दिया जायेगा। इसमें तो दूध की रखवाली बिल्ली से करवाने वाला मुहावरा चरित्रार्थ हो रहा है।कुछ पर्यावरण बचाने वालों को लगता है कि यदि संविधान में धारा 72 व 74 को संशोधित कर दिया जाय तो ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर इकाई बनकर अपना विकास कर सकती हैं। यह समझ भी काफ़ी सतही है। ग्राम पंचायतें किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भर नहीं हो सकती हैं। हमारे देश में राज्य आत्मनिर्भर व स्वतंत्र नहीं हैं। भारत में बिना आमूलचूल परिवर्तन के थोड़ा-बहुत सुधार तो हो सकते हैं। इससे व्यापक मेहनतकश जनता के जीवन की बदहाली नहीं रुक सकती है।

एक तरफ़ शहरों में जनता पानी के लिये तरसती रहती है, दूसरी तरफ़ होटलों में स्वीमिंग पूलों में फालतू पानी बहाया जाता है। एक तरफ़ गरीब आदमी को मकान या झोपड़ी बनाने के लिये एक पेड़ भी काटने नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ़ बड़ी-बड़ी कंपनियों को लगाने में हजारों पेड़ कटवाये जाते हैं।

गरीब व ग्रामीण लोग़ों को जंगलों के प्रयोग से वंचित रखने के लिये इको सेन्सिटिव जोन बनाये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देशी-विदेशी पर्यटकों के लिये राष्ट्रीय पार्क व सेनच्यूरियों में अय्याशी करायी जा रही है।

स्पेशल इकोनामिक जोन प्रदूषण के सारे मानकों को ठेंगा दिखाकर, सारे श्रम कानूनों का उल्लंघन करके, बिजली, पानी व करों में अधिकतम छूटें डकार कर मज़दूरों की कब्रस्थली बनते जा रहे हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां पूंजीपति वर्ग ने पर्यावरण व मज़दूरों को तबाह न किया हो। तथ्य तो यहां तक है कि भारत व चीन क्रमशः 2 व 4 प्रतिशत पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं जबकि अकेला अमेरिका 13 प्रतिशत पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए सरकारों व एनजीओ द्वारा फ़ैलाया भ्रम कि पर्यावरण को आम आदमी नुकसान पहुंचाते हैं, यह निराधार है। इसका पर्दाफ़ाश होना चाहीए।

-परचम

पूंजीवादी प्रचारतंत्र

मानव विकास के इतिहास में जब से वर्ग अस्तित्व में आये तब से हर विचार वर्गीय रहा है। वर्गीय समाजों में जो भी वर्ग प्रभुत्वशाली रहा है उसी के विचार समाज में हावी रहे हैं। मानव विकास के इतिहास में अब तक के वर्गीय समाजों की बात करें तो 20 वीं सदी के कुछ अपवादों (समाजवादी समाजों) को छोड़ दिया जाये तो सभी समाजों में कुछ मुट्ठी भर लोग़ों का बहुसंख्यक आबादी के ऊपर शासन रहा है। वैसे बात की जाय तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हज़ारों सालों से कुछ मुट्ठीभर लोग बहुसंख्यक आबादी के ऊपर शासन कैसे चला सकते?

जैसे हम अपने अनुभवों से देखते हैं कि किसी भी समाज में जो भी वर्ग सत्ता में होता है उस समाज के ज्ञान-विज्ञान, उत्पादन के साधन या जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी पर उस वर्ग का कब्ज़ा होता है जिससे वह अपने शासन को चलाने में कामयाब होता है। इसी संदर्भ में यहां पर जो बात की जा रही है वह आज के समय में जो प्रचारतंत्र या कहें तो पूंजीवादी प्रचार तंत्र है, वह किस तरह से अपने वर्ग की सेवा करता है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग का (भारतीय संदर्भों में) प्रचार तंत्र इसको चौथे स्तम्भ के रूप में स्थापित करता है। यह चौथा स्तम्भ अपने आकाओं के लिये दिन-रात काम करता है तथा शोषित वर्ग को गुमराह करके इनके लूट के तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।

वैसे तो यह इसके अपने चरित्र में चिन्हित है लेकिन इसको समझने के लिए एक छोटे उदाहरण की मदद ली जा सकती है। अभी 2 सितम्बर को पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव या कहें तो खत्म करने के विरोध मे हड़ताल हुई। जिसमें मज़दूरों ने देश स्तर पर अच्छी-खासी संख्या में भागीदारी कर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ़ अपने गुस्से का इजहार किया। खुद एसोचैम ने कहा कि इस हड़ताल में 25 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ। ये अलग बात है कि पूंजीपति वर्ग मज़दूरों की हड़ताल को इसी रूप में प्रचारित भी करता है कि नुकसान हुआ। तो कहा जा सकता है कि हड़ताल एक हद तक सफ़ल रही।

लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि पूंजीपति वर्ग के टुकड़ों पर पलने वाला मीडिया चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रोनिक इस हड़ताल को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं की। हां! अगर चर्चा थी तो हर बार की तरह कि लोग़ों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को आने-जाने में दिक्कत हुयी। जगह-जगह जाम लग गया। टीवी और अखबारों में जो छाया रहा वह था इंद्राणी वाला मामला जो पिछले पन्द्रह दिनों से लगातार 24×7 घन्टे चल रहा है। अगर गौर करें तो पिछले 20-25 सालों में जबसे कई आर्थिक नीतियां तेज़ी से लागू हुईं तथा मज़दूर मेहनतकशों पर हमले तेज़ हुये हैं। तब से पूंजीपति वर्ग इस तरह के प्रचार द्वारा इसको और भी सुनियोजित तरीके से अंजाम दे रहा है।

अगर पूंजीवादी मीडिया इंद्राणी या राधे मां जैसों का रिकार्ड 24 घण्टे महीनों तक चला सकता है लेकिन मज़दूरों के विरोध को थोड़ी सी भी जगह नहीं देता है तो इसी से पता चलता है कि पूंजीपति वर्ग आज कितना भयभीत है कि वह मज़दूरों की थोड़ी सी भी आहट से घबरा जा रहा है। और उसके लिए इतना चौकन्ना है कि एक तरफ़ इसके पालतू मीडिया तथा दूसरी तरफ़ इसके बहादुर सिपाहियों ने इसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रखी है।

इसी तरह से शासक वर्ग अपने निजाम को कायम रखने के लिये चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे कोर्ट हो हर संसाधन का इस्तेमाल करता है। मज़दूर वर्ग अगर इस लूट और शोषण पर टिकी व्यवस्था को टक्कर दे सकता है तो केवल अपनी वर्गीय एकता से।

– विजय

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब